पेयजल की भीषण समस्या : नगर निगम बेपरवाह

फरीदाबाद (म.मो.) शहर में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पानी की किल्लत से जूझ रहे कई कालोनीवासियों ने नगर निगम के आगे मटकाफोड़ प्रदर्शन भी किया, पर इसका नगर निगम के पदाधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा।

पेयजल की तो छोड़ें, सामान्य खारे पानी की सप्लाई कर पाने में भी नगर निगम विफल रहा है। इससे टैंकरों द्वारा पानी बेचने वालों की बन आई है। वे जम कर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। यही नहीं, बोतलबंद पानी का व्यवसाय करने वाले भी मालामाल हो रहे हैं। शहर में सैंकड़ों ऐसी कंपनियां कुकुरमुत्तों की तरह उग आई हैं जो अवैध रूप से भू-जल का दोहन कर उसे बीस लीटर के जारों में पैक कर बाज़ार और घरों में बेच रही है और वह भी मनमानी कीमतों पर। इससे लोग़ों को अपने बजट का अच्छा-खासा हिस्सा पानी पर खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन लोग़ मजबूर हैं। आखिर वे करें भी तो क्या करें? नगर निगम जहां पानी की आपूर्ति कर रहा है, वह पानी भी इतना खारा होता है कि पीने लायक तो कतई नहीं, नहाने व कपड़े धोने लायक भी नहीं होता।

पानी की किल्लत को देखते हुए निजी टैंकर वालों ने भी पानी के भाव बढ़ा दिये हैं। मजबूरी में कालोनीवासियों को बढ़ी हुई कीमतों पर भी पीने का पानी अलग एवं कपड़े धोने, बर्तनों की सफ़ाई करने एवं नहाने के लिए अलग से पानी खरीदना पड़ता है। टैंकरों का पानी जारबंद पानी से कुछ सस्ता पड़ता है, इसलिए निम्न व निम्न मध्यवर्गीय कालोनियों में बेचा जाता है, वहीं समृद्ध माने जाने वाले इलाकों में जारबंद पानी की बिक्री होती है।

गत वर्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से पानी का दोहन करने वाले पंपों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की पालना करते हुए प्रशासन ने तमाम अवैध रूप से पानी का दोहन करने वाले पंपों पर रोक लगा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि निजी टैंकरों द्वारा किये जाने वाला पानी का कारोबार बंद हो गया। लेकिन आम जनता पानी नहीं मिलने से त्राहि-त्राहि करने लगी। पहले तो उसे पैसे चुकाने पर पानी मिल जाता था, पर अवैध पंपों पर रोक लगा दिये जाने के कारण उन्हें पानी मिलना कठिन हो गया। नगर निगम ने अवैध पंपों के बंद कर दिये जाने से पहले पानी आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। अंततः हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद अवैध रूप से चलने पंप दुबारा शुरू हो गये। जनता ने राहत की सांस ली, क्योंकि फ़िर से उनके मुहल्लों में पानी बेचने वाले टैंकर आने लगे।

इस तरह देखा जाये तो नगर निगम पानी की सप्लाई कर पाने में बुरी तरह विफल रहा। इससे अवैध रूप से भू-जल का दोहन कर उसका व्यापार करने वालों की पौ-बारह रही।

आज अवैध रूप से भू-जल का दोहन कर पानी बेचने वाले दिल्ली तक अपना कारोबार कर रहे हैं। पानी के इस व्यापार में लागत तो नाम मात्र की होती है, पर मुनाफ़ा बहुत ही तगड़ा होता है। इस मुनाफ़े को देखते हुए शहर में एक जल माफ़िया उभर चुका है। नगर निगम प्रशासन एवं ज़िला प्रशासन से इसकी सांठगांठ तो है ही, राजनीतिक नेताओं का संरक्षण भी इन्हें प्राप्त है। इस संरक्षण के कारण ये बेख़ौफ होकर अपना धंधा चला रहे हैं।

पिछले दिनों शहर में बिकने वाले पचासों ब्रांड के पानी को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था, पर ढेर सारे सैंपलों में से सिर्फ़ एक सैंपल ही मानकों पर खरा उतरा। इससे पता चलता है कि लोग़ पैसे खर्च कर जिस पानी को आर.ओ. सिस्टम द्वारा परिशुद्ध मान कर पीते हैं, वह पानी भी सिर्फ़ फिल्टर्ड होता है और सुरक्षित पेयजल के मानकों पर खरा नहीं है।

पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। इस पर अमीर-ग़रीब सबका समान रूप से अधिकार होना चाहिए। पर विडंबना तो यह है कि आज की बाज़ारवादी व्यवस्था में यह भी ख़रीद-बिक्री की वस्तु बन कर रह गया है।

क्या नगर निगम नाली और नालों की सफ़ाई करवायेगा?

फरीदाबाद (म.मो.) बरसात के समय को देखते हुए भी नगर निगम नालियों-नालों की सफ़ाई से मुंह मोड़े हुए है। यद्यपि नगर निगम आयुक्त एम.एस.सहरावत ने कर्मचारियों को सख़्त हिदायत दे रखी है कि वे नालों की सफ़ाई के काम में पूरी तरह लग जायें, पर उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही है।

उल्लेखनीय है कि बरसात के मौसम में थोड़ी बारिश होते ही शहर के अधिकांश मुहल्लों और सेक्टरों में पानी भर जाता है। सीवर लाइन की सफ़ाई नहीं होने से उनका गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। लोग़ों को मजबूरीवश इसी मल-मूत्र से भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं-कहीं जल-जमाव तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बरसात रुकने के बाद भी घंटों तक पानी नहीं निकल पाता है। लोग़ों की यह मजबूरी है कि वे सीवर और नालों के सड़े पानी से हो कर गुजरें। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह समस्या आज की कोई नई नहीं है। यह समस्या बरसों पुरानी है। पर इसके समाधान की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। लोग़ भी इस बात को समझ चुके हैं कि बारिश होने के बाद उन्हें सड़कों पर लगे घुटने भर गंदे पानी से हो कर गुजरना है।

इस मूल-मूत्र से भरे गंदे पानी से न जाने कितनी बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां संक्रामक रूप धारण कर लेती हैं। कई स्थानों पर लगातार जल-जमाव के बने रहने से मलेरिया और डेंगू जैसी ख़तरनाक बीमारियों को पैदा करने वाले मच्छर पनपते हैं। हर साल बरसात के मौसम में और उसके बाद भी डेंगू नाम की जानलेवा बीमारी फैलती है जिसका एकमात्र कारण जमे हुए पानी में मच्छरों का पैदा होना है। डेंगू पर नियंत्रण के नाम पर प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य विभाग अच्छी-खासी राशि खर्च करता है। लेकिन अगर निगम ऐसी व्यवस्था कर दे कि जल-जमाव हो ही नहीं तो लोग़ डेंगू का शिकार होने से तो बचेंगे ही, इस पर नियंत्रण के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाता है, वह भी बचेगा।

बहरहाल, अभी-अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के बाद अलग-अलग वार्डों से कुछ नये चेहरे भी पार्षद के रूप में सामने आये हैं। मेयर बने अशोक अरोड़ा ने भी घोषणा की है कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनाव पूर्व सभी उम्मीदवारों ने जनता की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। इनमें जो जीत कर पार्षद बन चुके हैं, अब यह उनके जिम्मे है कि वे जनता की समस्याओं के हल की कितनी सुध लेते हैं। बरसात के मौसम में जनता की सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर जल-जमाव की है। अगर नव निर्वाचित पार्षद अपने-अपने क्षेत्र में इस गंभीर समस्या का समाधान करवा सकें तो जनता का उन पर भरोसा बढ़ेगा। लेकिन यदि पार्षद गण ऐसा करवा पाने में नाकाम साबित होते हैं तो जनता यह समझ कर संतोष कर लेगी नगर निगम में वह जिसे भी चुन कर भेजती है, वह निकम्मा ही साबित होता है।

जहां तक नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का सवाल है, वे निकम्मे, भ्रष्ट एवं अयोग्य तो हैं ही, इसके बारे में जनता को कोई संदेह नहीं रह गया है। पर जनता अपने द्वारा चुने गये पार्षदों से यह उम्मीद तो करती ही है कि वे निगम अधिकारियों पर अपना दबदबा बना कर उनके हित का काम करवायेंगे। नव निर्वाचित पार्षदों एवं मेयर अशोक अरोड़ा के लिये परीक्षा की घड़ी यही है। इस बरसात मे यदि नाली-नालों की सफ़ाई नहीं करवाई जाती है और जनता को पूर्ववत जल-जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि किसी काम के नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि वे उपरोक्त समस्या का समाधान कर देते हैं तो जनता का उन पर भरोसा कायम होगा और वह बढ़ेगा, अन्यथा वे कौड़ी के तीन साबित होंगे। जहां तक अफ़सरानों का सवाल है, वे काफ़ी मोटी खाल वाले हैं, पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद गण चाहें तो उनकी लगाम कस सकते हैं।

परिवहन व्यवस्था का नाश करने में जुटी सरकार

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जो सरकार पिछले 60 बरसों से चले-चलाये विभाग को ढंग से नहीं चला सकती, वह जेएलएनयूआरएम नाम के एक नये महकमे को क्या खाक चलायेगी? और फ़िर मकसद जनता को परिवहन सुलभ कराना है या केवल नेहरू खानदान का यशोगान करा है? यदि वास्तव में ही सरकार की नीयत जनता को एक बेहतर जन परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना होता तो ये एक-एक फ़र्लांग लंबे नाम के महकमे खड़े करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत है तो केवल परिवहन विभाग के प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त कर के बसों व कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था की। लेकिन सरकार के कुकृत्य स्वतः सिद्ध करते हैं कि इनका जनहित से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।

फ़रीदाबाद (म.मो.) बसों की कमी से बेहाल जनता का मज़ाक उड़ाते हुए पिछले दिनों सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पूरे ताम-झाम व नौटंकी करते हुए शहर की जनता को 15 वातानुकूलित वॉल्वो (लाल रंग की) बसें तथा 20 लो फ़्लोर (हरे रंग की) बसें प्रदान की। इस पूरी नौटंकी के लिये नगर निगम के सभागार के परिसर में बाकायदा समारोह कर के सरकार की उपलब्धियों का झूठा गुणगान किया गया। इन दोनों ही प्रकार की बसों के इंजन आगे की ओर न हो कर पीछे की ओर हैं। इनको चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिये हरियाणा रोडवेज़ के 20 ड्राइवर बंगलोर भेजे गये थे। ट्रेनिंग के बाद की परीक्षा को यद्यपि केवल 10 ड्राइवर ही पास कर पाये थे, लेकिन फ़िर भी इन सभी बीसों को इन बसों पर चढ़ा दिया गया। शेष 20 ड्राइवर भी राज्य परिवहन के स्थानीय डिपो से ही लिये गये।

पाठकों की जानकारी के लिये बता दें कि ये बसें हरियाणा रोडवेज़ की न हो कर केंद्र सरकार की एक योजना - जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत दी गई हैं। योजना के मुताबिक अभी ऐसी 450 बसें और आनी हैं और इनको चलाने के लिए बाकायद अलग से एक महकमा खड़ा किया जायेगा। 35 बसें तो आन खड़ी हुईं, लेकिन इन्हें चलाने वाला महकमा अभी तक बना नहीं, ड्राइवर-कंडक्टर तक भर्ती किये नहीं। लेकिन सरकार ने ड्रामा तो रचाना था, लिहाज़ा इन बसों के लिये 40 ड्राइवर-कंडक्टर फ़रीदाबाद डिपो से ले लिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि डिपो की चलती हुई 35 बसें ड्राइवर-कंडक्टर के अभाव में खड़ी हो गईं।

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि लाल रंग वाली वाल्वो बस की कीमत है 85 लाख और ये स्वीडन से आयात की गई हैं। हरे रंग वाली बसों की कीमत 60 लाख रुपये है, जबकि साधारण बसों की कीमत 12 से 13 लाख रुपये है। इस हिसाब से उक्त 35 बसों के लिये 2475 लाख खर्च किये गये हैं, इसी रकम में 200 साधारण बसें आ सकती थीं, जिससे शहर की जनता को वास्तविक लाभ हो सकता था। लेकिन इस नाटकबाज सरकार का लक्ष्य जनता को राहत पहुंचाना कतई नहीं है। इनका असल मकसद तो देशी-विदेशी बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। पिछले दिनों भारत सरकार ने बस व ट्रक निर्माता कंपनियों को मंदी से उबारने के लिये 10,000 करोड़ का पैकेज रखा था, उसी पैकेज में से यह लुटाई हो रही है। इसमें से हरियाणा को 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार को यदि थोड़ी-सी राष्ट्रीय हित की चिंता होती तो वह इस तरह की नाटकबाज़ी के बजाये 12-13 लाख रुपये वाली बसें खरीदती जिससे बड़ी संख्या में बसों का निर्माण होता, रोजगार बढ़ता और जनता को सवारी के लिये अधिक बसें उपलब्ध होतीं। प्रश्न यह भी उठता है कि जब अपने देश में बसें बन रही हैं तो स्वीडन से आयात करने की क्या आवश्यकता थी? जाहिर है, मोटे कमीशन की लालच और विदेशी दबाव में सरकार यह सब कर रही है।

निकम्मी सरकार से रोडवेज़ का एक महकमा तो चल नहीं रहा, दूसरा महकमा खड़ा करने की बात करते हैं। अकेले फ़रीदाबाद में 1000 बसों की जरूरत है जबकि आज उपलब्ध हैं मात्र 235, और इनमे से भी अधिकांश की हालत खस्ता है। इनको चलाने के लिये कम से कम 300 ड्राइवर व इतने ही कंडक्टर चाहियें, लेकिन उपलब्ध हैं केवल केवल 240 ड्राइवर व 250 कंडक्टर। इसके चलते इन लोगों को न तो साप्ताहिक अवकाश मिल पाता है, न कोई अन्य छुट्टी तथा जो बसें खड़ी रहती हैं वे अलग से। 1990 के बाद से वर्कशॉप में एक भी मिस्त्री भर्ती नहीं हुआ है, लिहाज़ा उस वक्त के 48 में से घट कर 20 रह गये हैं। पूरी वर्कशॉप को चलाने के लिये पढ़े-लिखे इंजीनियर को वर्क्स मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो कई वर्षों से यहां नहीं है। ऐसे में वर्कशॉप कैसे चलेगी, बसों पर कैसा काम होगा, समझना कठिन नहीं है। इतना ही नहीं, स्टोर परचेज़ अफ़सर तथा ट्रैफ़िक मैनेजर के पद भी काफ़ी समय से खाली पड़े हैं। कई बार तो डिपो के जनरल मैनेजर का पद भी खाली रह जाता है। इन सब बातों से पता चलता है कि सरकार अपने हाथ में लिये कामों के प्रति कितनी उदासीन व गैरजिम्मेदार है। दरअसल, इस सबके पीछे राज नेताओं की यही सोच है कि उनके घर से क्या जा रहा है? सरकारी काम है, सत्यानाश हो रहा है तो होता रहे, जनता भुगत रही है तो भुगतती रहे।

ऐसे में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जो सरकार पिछले 60 बरसों से चले-चलाये विभाग को ढंग से नहीं चला सकती, वह जेएलएनयूआरएम नाम के एक नये महकमे को क्या खाक चलायेगी? और फ़िर मकसद जनता को परिवहन सुलभ कराना है या केवल नेहरू खानदान का यशोगान करना है? यदि वास्तव में ही सरकार की नीयत जनता को एक बेहतर जन परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना होता तो ये एक-एक फ़र्लांग लंबे नाम के महकमे खड़े करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत है तो केवल परिवहन विभाग के प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त कर के बसों व कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था की। लेकिन सरकार के कुकृत्य स्वतः सिद्ध करते हैं कि इनका जनहित से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।